



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 1989/माघ 5, 1910

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 1989/MAGHA 5, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रहित रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं 94 आई टी सी (पी एन) 88-91

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1989

विषय — 1988-89 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत  
उपस्कर और सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग शर्तें — (1) क्षेत्रीय  
केन्द्र क्षेत्र में चिकित्सा उपस्कर के सुधार के लिए 641  
मिलियन येन और (2) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्व-  
विद्यालय के शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपस्कर के सुधार के लिए  
611 मिलियन येन।

फाइल सं आई पी सी 23(51) 88-91—1988-89 वर्ष के लिए  
जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत (1) क्षेत्रीय केन्द्र क्षेत्र में चिकित्सा  
उपस्कर के सुधार के लिए 641 मिलियन येन (2) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय  
खुला विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपस्कर के सुधार के लिए  
611 मिलियन येन के उपस्कर और सेवाओं को प्राप्ति करने वाली शर्तें  
जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं सूचना के लिए  
प्रसिद्धित की जाती हैं।

के. जी. हरनोराया, मुख्य नियंत्रक, आयात नियंत्रण

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं 94 आई टी सी (पी एन)  
88-89 दिनांक 25-1-89 का परिशिष्ट

क्षेत्रीय केन्द्र क्षेत्रों के चिकित्सा उपस्कर के सुधार हेतु वर्ष  
1988-89 के लिए 641 मिलियन येन की जापानी अनुदान  
सहायता के अन्तर्गत क्षेत्रीय केन्द्र क्षेत्रों हेतु चिकित्सा उपस्कर  
की खरीद करने और आवश्यक सेवाओं को स्थापित करने  
उपस्कर का भारतीय बन्वर्गाहों पर परिवहन और उनके आन्त-  
रिक परिवहन के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तें।

खंड-1 सामान्य शर्तें

1 (1) वर्ष 1988-89 के लिए जापानी अनुदान सहायता की  
641 मिलियन येन धनराशि को निम्न कार्य के लिए प्रयोग करने का  
निष्पत्ति किया गया है —

- (1) क्षेत्रीय केन्द्र क्षेत्रों के लिए फीट स्केल्स और प्रमुख उपस्कर  
और आवश्यक सेवाओं की स्थापना करने के लिए आयात  
उपस्कर का परिवहन करने के लिए (406.4 मिलियन येन)।
- (2) मद्रास केन्द्र सम्मान के लिए डायग्नोस्टिक उपस्कर और  
आवश्यक सेवाओं की स्थापना के लिए आयात/उपस्कर का  
परिवहन करने के लिए (234.6 मिलियन येन) 234.6

मिलियन येन में से 26.5 मिलियन येन की धनराशि को जापान से परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए रखा गया है।

1(2) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयात लाइसेंस जिसकी धनराशि 705 मिलियन येन (सी.आई.एफ.) से अधिक नहीं होती चाहिए और उसे आयातक के नाम में और उस पर 1988-89 के लिए जापानी अनुदान सहायता "641 मिलियन येन" अभिलेखित किया जाना चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जे.एन." कोड होगा। तथापि, खूले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए किसी आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

1(3) इस सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपस्कर, और सेवाओं की अधिप्राप्ति जापान/भारत से की जाए। खरीद आदेश केवल जापानी संभरकों को ही दिये जाएं।

1(4) आयात लाइसेंस को सी.आई.एफ. आधार पर जारी किया जाएगा और प्रारंभ में इसकी वैधता 31-3-89 तक की होगी।

1(5) संविदा में जापानी संभरक द्वारा भारतीय बैंक, टोकियो को नौवहन प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण पर नकद प्रदायगी करने की व्यवस्था होगी चाहिए। इसमें वितरण अवधि के लिए निम्न प्रकार से उल्लेख किया जाए। "वितरण को 15-3-1989 तक पूरा किया जाए"।

1(6) ठेके की जहाज पर्यन्त निशुल्क लागत सीमा भाड़ा मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और उसमें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो, तो वह शामिल नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में संविदा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा में अभिव्यक्त नहीं किया जाना चाहिए।

जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य और भाड़ा राशि को अलग अलग दर्शाया जाए परन्तु संविदा में यह स्पष्टीकरण कर दिया जाना चाहिए क्या भाड़ा वास्तविक आधार पर अदा किया जायगा या भाड़ा प्रभारों, वास्तविक प्रभारों को मद्दे नजर रखे बिना ही अदा किया जाएगा।

1(7) खरीद संविदा केवल जापानी येन में और जापानी राष्ट्रिकों के साथ की जाए।

1(8) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति खूली निविदा के आधार पर की जाएगी और वह जापानी संभरकों तक सीमित होगी और ठेका निम्नतम मूल्यांकन वाले एवं तकनीकी रूप से स्वीकार्य बोलीकार को दिया जाएगा। यदि किसी मामले में यह सुझाया जाता है कि इस अनुदान के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति सीधी बातचीत के जरिए की जाए तो आर्थिक कार्य विभाग (जापान, अनुभाग), वित्त मंत्रालय के माध्यम से जापान सरकार की पूर्ण अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

खंड 2—संभरण ठेके में निम्नलिखित उपबन्धों को विशेषतः शामिल किया जाए।

2(1) ठेके की व्यवस्था वर्ष 1988-89 के लिए 641 मिलियन येन अनुदान सहायता के संबंध में 8 नवम्बर, 1988 को हुए भारत सरकार और जापान सरकार के बीच समझौते के बीच समझौते के अनुसरण में दोनों सरकारों की स्वीकृति के अधीन की जाए।

2(2) संभरकों को प्रदायगी के लिए प्राधिकार (ए/पी) जो कि नियंत्रक, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा 1988-89 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत भारतीय बैंक टोकियो के नाम में जारी किया जायगा।

2(3) जापानी संभरक ऐसी सूचना और प्रलेखों को जो कि एक और भारत सरकार की ओर से और दूसरी ओर जापान सरकार की ओर से अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने को सहमत होगा।

2(4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतलदान व्यवस्था के लिए सहमत हो जाता है तो वह पोतलदान के कम से कम छः मन्हा पूर्व निहित माल के वितरण कार्यक्रम के संबंध में भारतीय दूतावास को सूचित करेगा ताकि उचित व्यवस्था की जा सके। अपवाद के मामलों में यदि आयातक चाहे तो इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान का आवश्यक विवरण देने हुए एक तार आयातक को और उगकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजने के लिए सहमत होना चाहिए।

खंड 3—भारत सरकार तथा जापान सरकार द्वारा ठेके की स्वीकृति।

3(1) जैसे ही आदेशों का अन्तिम रूप दे दिए जाएं लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतियां जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए कथ आदेश के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की 5 प्रतियां (एक मूल और 4 फोटो कॉपियां) या सभी प्रकार से फोटो कॉपियां जिसके साथ निविदा मूल्यांकन रिपोर्ट की दो प्रतियां और दो प्रतियों के साथ अनुबंध 1 के प्रपत्र में "ए/पी जारी करने के लिए आवेदन पत्र" में प्रवर सचिव (टी.सी.) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपयुक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक उपान्तरणों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3(2) वित्त मंत्रालय (डी.ई.ए.), जापान अनुभाग 1988-89 के लिए 641 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन चिन्तन देने के लिए संविदा की दो प्रतियां जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा, और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक-एक सेट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारतीय दूतावास, टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3(3) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का जापान अनुभाग, नार्थ ब्लॉक इसके बारे में सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सूचना देगा जो कि जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को अनुबंध 2 के अनुसार एक "भुगतान प्राधिकार" (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार (ए/पी) की प्रतियां भारत का दूतावास टोकियो आयातक, भारत में आयातक का बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी।

3(5) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से (ए/पी) में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी संभरक को अपने बैंकों के माध्यम से रिलीज करेगा।

3(6) जापानी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को वेब बैंकिंग प्रभारों के भुगतान की व्यवस्था भारत का दूतावास, टोकियो द्वारा आयातक विभाग की ओर से की जाएगी। इस प्रभारों के समान रुपये की प्रदायगी सी.ए.ए. एंड ए., नई दिल्ली से उपयुक्त सूचना प्राप्त होने पर आयातक विभाग द्वारा लेखा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली की की जाएगी।

खंड-4—रफ़ा जमा करने के लिए उत्तरदायित्व।

4(1) मूल विनियम पोतपरिवहन प्रलेख निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुबंध 1(ग) में उल्लिखित है की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के वे

विनियम सेट केवल इस बात का सुनिश्चित कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी सभरक को बुकार्ड गई येन भुगतान की धनराशि के बराबर रुपया 12-10-1976 की सार्वजनिक सूचना सं. 103/आई टी सी (पी एन)/76 द्वारा यथासंशोधित 31-5-1974 की सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74 की शर्तानुसार सरकारी खाने में जमा कर दिया गया है।

येन भुगतान की धनराशि के बराबर रुपये की गणना करने के लिए अपनार्ई जाने वाली विनियम वर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-1976 में निर्धारित मुद्रा विनियम की मिश्रित वर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्राविनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले वेय धनराशि सरकारी खाते में विधिवत रूप से जमा कर दी गई है। आयातक को भी अपने बैंकरो से दस्तावेज लेने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वेय धनराशि सरकारी खाते में ठीक से जमा कर दी गई है। आयातक की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि असाधारण परिस्थितियों में सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल का विवरण प्राप्त कर लेन पर धनराशि सरकारी लेख में शीघ्र जमा कर दी गई है। यदि आयातक माल की सुपूर्दगी लेन से पहले सरकार को वेय धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसे आगे और प्राधिकार पत्र जारी करना रोक दिया जाए। और मामले की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात को भी जाननी चाहिए ताकि ऐसे आयातक को आगे और लाइसेंस जारी न किया जा सक। केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए गए ऐसे आयातों के संबंध में कोई ब्याज प्रभार लागू नहीं होगा। जिस लेखा शीप में उपयुक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज 844-सिविल डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेक्ट्र एण्ड परचेजिज अण्डर ग्रांट एंड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान" फार 1988-89' शान्ट फार परचेजिज आफ मोडकल इक्विपमेंट एंड सर्विसेज नैसगरी फार वी इन्स्टालेशन/ट्रांसपोर्टेशन आफ इक्विपमेंट है।

4(2) चालान के बाए कोने में कोड सं. 513000009 दर्शाते हुए उपयुक्त धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, सीत हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके अनुषंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डीकर्ता) में प्राप्त एक हुंडी (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया तीन हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डो ग्राह्य और प्रापल) में सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 30-8-1964, सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-1968 और 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-1971 सं. 74/आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-1974 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-1976 में निर्धारित सरकारी लेखों में जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए।

4(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के अन्दर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी उपयुक्त निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा भागी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरो को इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "वन परेषण

और प्राधिकारी (यदि कोई हो के पूर्ण व्यौर) में निरपवाद रूप से निहित किए गए है खजाना चालान में निम्नलिखित व्यौर निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए —

(व) वित्त मन्त्रालय भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए.पी.) की संख्या और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनार्ई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) जापानी सभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) बुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए ये गिना गया है।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

तत्पश्चात् सी.ए.ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का सर्वर्ष वेते हुए और बीजक तथा पीत परिवहन दस्तावेजों की प्रतियों को सलग्न करने हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी.ए.ए. एण्ड ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी.—भारत में आयातक के बैंक के यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से आयातकी की सूचना और विनियम पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी.ए.ए. एण्ड ए. वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

4(4) भारत में सम्बद्ध बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए। अपेक्षित "एल" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड 5—विधि प्रावधान

(1) अनुदान सहायता के उपयोग की रिपोर्ट

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलदानों और उसके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान होना बाकी है, उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी.ए.ए. एण्ड ए., आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

आयातक को चाहिए कि वह इन अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल से संबंधित किसी ऐसी विशेष शर्त से सभरक को अज्ञात कराए जो समझौते का पालन करने में सभरक को पर प्रभाव डालती हो।

5(2) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि आयातक और सभरक के बीच में यदि कोई विवाद होगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व सभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें-साफ साफ "भुगतानों के नियमों में" अनुबंध-1 में आयातक द्वारा दर्शायी जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तों के की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

5(3) भावी अनुदेश

आयातों या उसके संबंध में उठने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1988-89 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आयातों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निदेशों या आदेशों का आयातक को तुरन्त पालन करना होगा।

5(4) प्रतिश्रमण या उत्सर्जन

उपयुक्त खंडों में निर्धारित की गई शर्तों के प्रतिश्रमण या उत्सर्जन करने पर आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी।

## 5(5) अनुबन्धों की सूची

- अनुबन्ध 1 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए.पी.) जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र ।
- अनुबन्ध-2 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र ।

अनुबन्ध-1

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र” संख्या

दिनांक

सेवा में

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,  
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,  
पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय:--1988-89 के लिए 641 मिलियन येन की जापानी सरकार सहायता के अन्तर्गत ऋणकारी उपस्कर और आवश्यक सेवाओं की स्थापना हेतु खरीद करना/उपस्कर का परिवहन करना ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपर्युक्त उपस्कर के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित शर्तों के अधीन है जससे कि आप जापान सरकार के पक्ष में बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें:-

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।
- (ख) आयात लाइसेंस की सं., दिनांक और मूल्य और वह स्थिति जब तक यह वैध है ।
- (ग) अधिप्राप्ति के तरीके । क्या यह प्रत्येक खरीद पर आधारित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित है । इस मामले में कारणों सहित यह निदिष्ट करना है कि क्या सविदा का निर्णय उपर्युक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण ।
- (ङ) माल का उद्योग देश ।
- (च) सविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) ।
- (छ) यदि कोई हो तो, भारतीय रुपए में भारतीय एजेंट के कर्माशन की धनराशि (येन में) ।
- (ज) वह शुद्ध लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है ।
- (झ) संभरकों के साथ की गई सविदा का नाम और दिनांक ।
- (ट) संभरक का नाम और पता ।
- (ड) वे भुगतान शर्तें और संग्रहित स्थिति जिनकी सविदाओं के अन्तर्गत भुगतान वेय होंगे ।
- (ठ) सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियां ।
- (ड) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करने समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सैट की संख्या और उनका निपटान वसति हुए) ।
- (ढ) पोतलदान अनुदेश (बाहन्तरण/पार्टिशपमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं निदिष्ट की जाए ।

(ग) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

(त) आयातक द्वारा वचनबद्धता:--“हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को वेय धनराशि के समतुल्य रुपए की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रिया विधि से और प्रचलित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे । माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक परेपण की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्ण राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी । विदेशी राष्ट्रों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक का भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी ।”

भवदीय,

अनुबन्ध-2

भुगतान के लिए प्राधिकरण सं. -----

संख्या -----एक

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

बैंक आफ इंडिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय:--1988-89 के लिए 641 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत उपस्कर और आवश्यक सेवाओं की स्थापना हेतु खरीद करना/उपस्कर का परिवहन करना । प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ की किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा संलग्न व्यौरे के अनुसार सर्व शर्तों को -----को -----धन राशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पकती वे बारे में संभरक का सूचना दे और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक भारत राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए ।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा ।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज संभरकों एवं बैंकों के प्रभाव को भेजने आदि के माड़े सहित अशा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े भारतीय दूत काम टोकियो द्वारा अशा किए जाएंगे ।

5. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है त इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए ।

6. इस मंत्रालय की विवेक अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है ।

7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र -----तक वैध रहेगा

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक -----को उनके पत्र सं. -----  
दिनांक -----के संदर्भ में / उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे बैंकों से परामर्श दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व अपने बैंकों के माध्यम से रुपए निक्षेप आदि को जमा करवाने की व्यवस्था करें। यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से मूलपरिवहन दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमा शुल्क प्राधिकारियों और पत्तन के प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी सीधे ही प्राप्त कर ली हो, तो वहाँ सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशि जमा करवाना चाहिए। विदेशी सभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही भुगतान के लिए बांझ अनुमोदित किए जाते हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा देनी चाहिए। शीघ्र ही और सही रूप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग शर्तों में उल्लिखित कार्रवाई की जाएगी।

2. आयातक का बैंक -----उत्तसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी संभरकों को येन भुगतान के समतुल्य रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। सभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8--आई टी सी (पी एन) /76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समयसमय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी सभरकों को भुगतान करने की तिथि की यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यदि इस दर में कोई परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना सुन्त दी जाएगी। इस बात का मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सीमाशुल्क निकासी के लिए आयातक का दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कराई जाती है।

बालान के दाएँ कोने में कोड नं. 5130000009 वर्गित हुए ये धनराशिया या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, नोम हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया को किसी शाखा, या इसकी अनुपंगों सस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली 6 (आदेशित और आदाता) के नाम में और उसकी वेब वर्तन हुण्डों के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 233--आई टी सी (पी एन)/ 68, दिनांक 24-10-68, सं. 132--आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74--आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103--आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें राशि जमा की जाएगी वह "के डिवाइजिट्स एण्ड एडवांसिज 843 सिविल डिपोजिट्स फार परवेजिस एटसैकू एत्राड परवेजिस/प्राष्ट एण्ड फोम सी गवर्नमेंट आफ जापान फार 1988-89 अन्डर डिटेल्ड हेड" "641 मिलियन येन ग्रान्ट एण्ड फार परवेज आफ मैडिकल इक्विपमेंट एण्ड मर्विस नेसेसरी फार इन्फान्टलेज/ ट्रान्सपोर्टेशन आफ इक्विपमेंट"।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132--आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें बालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए प्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी--

3. लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)  
पहली भजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,  
संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर सकेतिन सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्गित हुण्डों द्वारा प्रेषित करना है उसकी

सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा व्योम इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार सभरक के बैंक के खातों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्च और बैंक आफ इंडिया, टोकियो बांच के अन्य खर्च इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा आयातक विभाग की ओर से भ्रदा किए जाएंगे। इन प्रभारों के समतुल्य रुपये की गणना उपर्युक्त ढंग से की जाएगी और इसे नियंत्रक लेखा विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को वेध धनराशि के रूप में जमा किया जाएगा जिसके सबध में सी ए ए एंड ए विभाग को उपयुक्त बीजक जारी करेगा।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवग मन्त्रि, (जापान शाखा), वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को उनके आई टी सं. ----- दिनांक ----- के संदर्भ में।

(लेखा अधिकारी)

611,000,000 मिलियन येन (छ. सौ ग्यारह मिलियन येन) की जापानी अनुदान सहायता 1988-89 के अतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (आई. जी. एन. ओ. यू.) के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपस्कर की खरीद और उपस्करों को लगाने परियोजना के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग शर्तों।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें --

1. (i) 1988-91 के लिए 611 मिलियन येन (लागत एवं भारा) की जापानी अनुदान सहायता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (आई. जी. एन. ओ. यू.) द्वारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपस्करों की खरीद और उपस्करों को लगाने परियोजना के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए जापानी संभरकों को किए जाने वाले भुगतान के वित्तपोषण के लिए है।

1. (ii) आयातक के नाम में कुल 672 मिलियन येन (लागत-बीमा-भाड़ा) की धनराशि तक के लिए आयात लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए और इस पर "1988-91 के लिए येन 611 मिलियन जापानी अनुदान सहायता" शब्द अंकित होने चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड "एम/जेएन" होगा/खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आने वाली मर्च के लिए किसी आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

1. (iii) आयात लाइसेंस के मद्दे विदेशी मुद्रा का प्रेषण अनुमेय नहीं होगा किन्तु बैंक इंडिया टोकियो को जो प्रभार सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं, वे इसमें शामिल नहीं हैं। भारतीय एजेंट का कमिशन यदि कोई हो तो, उसका भुगतान भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य का ही एक अंग समझें जाएंगे और अतः लाइसेंस पर ही प्रमाणित किए जाएंगे।

1. (iv) इस अनुदान सहायता के अतर्गत उपस्कर और सेवाएं केवल जापान/भारत से ही अधिप्राप्त किए जाने चाहिए। अन्य आदेश केवल जापानी संभरकों को ही दिए जाएंगे।

1. (v) आयात लाइसेंस लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किए जाएंगे जिनकी वैधता 31-3-1989 तक होगी।

1. (vi) संविदा में भुगतान की व्यवस्था नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतपरिवहन दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर करनी चाहिए। वितरण की अवधि निम्न प्रकार में होगी :—

"वितरण 15-3-1989 तक पूर्ण करना है।"

1. (vii) संविदा का मूल्य (लागत एवं भाड़े जहाज पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर (येन में) येन का ग्रंथ हटा देना चाहिए (प्रशंसित किया जाना चाहिए और भारतीय अधिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो उसे निकाल देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में संविदा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा में प्रशंसित नहीं किया जाना चाहिए।

जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत एवं भाड़ा राशि अलग से दर्शाई जानी चाहिए, किन्तु संविदा में यह स्वतः स्पष्ट होना चाहिए कि भाड़े का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जायेगा अर्थात् उसमें दर्शाया गया भाड़ा वास्तविक प्रभारों के अनिश्चित भुगतान की राशि होगा।

1. (viii) अन्य संविदा जापानी राष्ट्रों द्वारा या जापानी राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित न्यायिक जापानी व्यक्तियों के साथ येन में की जानी चाहिए।

खण्ड-2 संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान स्पष्ट रूप से समाविष्ट होना चाहिए।

2. (i) ठेके की व्यवस्था 1988-89 के लिए येन 611 मिलियन के अनुदान सहायता के अनुसार भारत और जापान की सरकारों के बीच हुए 8 नवम्बर, 1988 को हुए समझौते के अनुसार होनी चाहिए और दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी।

2. (ii) संभरणों को भुगतान "भुगतान के प्राधिकार" (ए/पी) के माध्यम से किए जाएंगे। जो 1988-89 के लिए जापान अनुदान सहायता के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूको बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001 द्वारा जारी किए जाएंगे।

2. (iii) जापानी संभरण ऐसी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे जो एक और भारत सरकार एवं दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित होंगी।

2 (iv) जापानी संभरण भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत हैं और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को आर्थिक माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा। और पोत-लदान से कम से कम छः सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहाँ आयातक इच्छुक हो, सूचना को इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरण का प्रत्येक पोत-लदान के पश्चात् आवश्यक व्योरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-3 भारत और जापान की सरकारों द्वारा संविदा का अनुमोदन

3 (i) जैसे ही प्रावधानों को अंतिम रूप दे दिया जाए, साइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा की पांच प्रतियां (मूल और 4 फोटो प्रतियां) जापानी संभरणों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय प्रावधान के साथ जापानी संभरण द्वारा लिखित रूप में पुष्टि-करण आदेश के साथ अनुबंध-1 के प्रपत्र "(ए/पी) जारी करने के प्रावधान" की दो प्रतियों सहित अवर सचिव (टी सी) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, मार्च. ब्लाक नई दिल्ली को भेजी जाएगी। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत में आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3. (ii) वित्त मंत्रालय (बीईए) जापान अनुभाग, 1988-89 के लिए 611 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्तदान देने के लिए संविदा की दो प्रति जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (i) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक सेट सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास टोकियो को भी भेजेगा।

3. (iii) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, मार्च ब्लाक को उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यूको बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को देगा जो कि जापानी संभरण को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को अनुबंध-2 के अनुसार एक "भुगतान प्राधिकार-पत्र" (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रतियां भारत का दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी।

3. (iv) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो, जापान सरकार, भारत का दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से जापानी संभरण को अवगत करायेगा।

3. (v) पोत लदान करने के बाद जापानी संभरण अपने बैंकों के माध्यम से (ए/पी) में उल्लिखित वस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि वस्तावेज सही पाये गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो को वस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को जापानी संभरणों को अपने बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा।

3. (vi) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्च भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत में आयातक से संबंध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को धन परेषित करके निर्णीत किये जाएंगे।

खण्ड-4 खपता जमा कराने का उत्तरदायित्व

4(i) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरूपण रूप से बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबंध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या अनुबंध-1 के (ण) में उल्लिखित किनी भी राष्ट्रीकृत बैंक की शाखा होगी, उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबंध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरण को चुकाई गई येन धनराशि के बराबर खपता व्याज प्रभार सहित जापानी संभरण को भुगतान कर दिया गया है और इस धन-राशि पर जापानी संभरण को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से वास्तविक खपता जमा करने की तिथि की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से हिसाब लगा कर व्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-मार्चटीसी(पीएन) 83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार सरकारी लेखों में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन जापानी संभरण को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखों में खपता जमा किया जाता है, के लिए देय है, बखि ए सार्वजनिक सूचना सख्या 103-मार्चटीसी(पीएन) 76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-मार्चटीसी(पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 येन भुगतान के समस्त खपत की गणना करने के लिए अपनाई गई विनियम की दर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8-मार्च टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में यथा-निर्धारित मुद्रा विनियमय की प्रचलित मिश्रित वर या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी गई है। इस संबंध में और व्याज की दर के संबंध में भी कोई भी परिवर्तन जैसे ही आवश्यक होगा, अधिसूचित किया जाएगा। संबंध भारतीय बैंक का इस बात का सुनिश्चित करने का शायद होगा कि आयातकों को आयात वस्तावेज सोपने से पूर्व देय धनराशि सरकारी लेखों में सही रूप से जमा कर दी गई है। आयातक को भी यह सुनिश्चय करना चाहिए कि अपने बैंक से दस्तावेज लेने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखों में सही रूप से जमा करा दी गई है। यह सुनिश्चय करना आयातक

को जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी लेखे में उस समय भी तुरन्त जमा करा व जबकि वे विशेष परिस्थितियों में सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माण की मूयुईगी प्राप्त करते हों। उस मामले में जब आयातक सरकार को देय धनराशि माण छुड़वाने से पूर्व जमा करवाने में अममर्थ होता है तो उसे आगे ए/पी जारी करना रोक दिया जाए और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को तथ्यों से अवगत करवाया जाए जिससे ऐसे आयातक को आगे कोई आयात लाइसेंस जारी न किया जाए। लेखा शीर्ष जिनमें उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के" डिपोजिट्स एंड एडवाइज-843-निविन डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेज एटसेट्टा एंडा परचेज एंडर प्रॉट एंड फ्राम वि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1988-89 द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय ग्रांट फार परचेज आफ वि एड्युकेशनल टेक्नोलोजी इन्विपमेंट एण्ड सर्विजिज नेससरी फार वि इन्स्टालेशन आफ दी इक्विपमेंट/ट्रांसपोर्टेशन आफ इक्विपमेंट वाई दी आई जी एन ओ यें यू।

4(ii) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में चालान के दाहिने कोने में कोड सं. 5130000009 दर्शाने हुए या स्टेट बैंक आफ इंडिया, लोम हजारी, दिल्ली में या यदि यह संभव न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया, लोम हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आदात) के नाम और उसको देय स्टेट बैंक आफ इंडिया या इसकी सहायक शाखा या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (आदेशक) से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-1968 और सं. 132-आई टी सी (पी एन)/73, दिनांक 5-10-1971, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1976 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 में दिए गए तरीके से सरकार के खाते में नकद जमा करानी चाहिए।

4(iii) भारत में संबंध बैंक भी उपर्युक्त निर्धारित विधि के अनुसार सरकार द्वारा मांग करने पर 7 दिनों के भीतर सेवा प्रदायों के निमित्त अतिरिक्त निक्षेप भेजेगा। चालान के विभिन्न कालम भरते समय आयातकों उनके बैंकों को यह सूनिश्चित कर देना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 और सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ की जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना चालान के "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्योरे" कालम में निरपवाद रूप से निविष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के "ए/पी" (भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र) की सं. एवं दिनांक।

(ख) येन सुझा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनवाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) जापानी संभरक को भुगतान की तिथि।

(घ) भुगतान किए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई है।

(ङ) निक्षेप की गई कुल धनराशि।

(ब्याज की गणना जापानी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में तुल्य रुपया जमा कराने की तिथि तक करनी है।

उसके पश्चात् सी ए ए एण्ड ए द्वारा जारी किए गए एपी (भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र) का संवर्ध देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन वस्तुओं को संलग्न करने हुए खजाना चालान, रुपया जमा करने का साध्य वेते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :— भारत में आयातक के बैंकों को यह सूनिश्चित कर देना चाहिए।

कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो से भुगतान की सूचना और विनिमय पोत परिवहन वस्तुओं की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर रुपया निरपवाद रूप से जमा कर दिया गया है और यह कि इसके तुरन्त बाद इसकी सूचना सी ए ए एण्ड ए, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को दे दी गई है।

4(iv) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की सुझा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, सम्बर्ध को भेजना चाहिए।

#### खण्ड-5 विविध व्यवस्थाएं

##### 5(i) अनुदान सहायता के उपयोग पर रिपोर्ट

आयातक को पोसलवान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में एपी जारी हो जाने के पश्चात् एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, यू को बैंक बिल्डिंग, समद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

आयातक की इस अनुदान सहायता के अधीन सबों के आयात के संबंध में उन विशेष प्रावधानों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माण के लेन-देन में संभरक पर प्रभाव डालती हों।

##### 5(ii) विवाद

यह समझ देना चाहिए कि आयातकों और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तर दायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें आयातक द्वारा अनुबन्ध-1 में "भुगतान की शर्तों" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट करनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद निपटाने से संबंधित व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

##### 5(iii) भविष्य अनुदेश

जापान से 1988-89 के लिए अनुदान सहायता के अधीन आयातों से उत्पन्न या उनके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी भी मामले या सभी मामलों के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों या आदेशों और सभी दायित्वों को आयातक को तुरन्त करना होगा।

##### 5(iv) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त अनुच्छेदों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

##### 5(v) अनुबन्धों की सूची

अनुबन्ध-1 एपी जारी करने के लिए आवेदन पत्र

अनुबन्ध-2 एपी का प्रपत्र

अनुबन्ध-1

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र”

संख्या

दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,  
यूको बैंक लिमिटेड, प्रथम संजिल,  
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय:— 1988-89 के लिए 611 मिलियन येन की जापानी अनुदान  
सहायता के अन्तर्गत उपस्कर स्थापित करने परियोजना के लिए  
आवश्यक शैक्षिक प्रौद्योगिक उपस्करों और सेवाओं—  
का आयात।

महोदय,

उपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपर्युक्त उप-  
करणों के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ध्याना भेजते हैं  
जिससे कि आप संबंध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया, टोकियो  
को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी) जारी कर सकें:—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता।
- (ख) आयात लाइसेंस की सं., दिनांक और मूल्य और यह तिथि  
जब तक यह वैध है।
- (ग) अधिप्राप्ति के तरीके। क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित  
है या सीमित मुन्नी निविदा पर आधारित है। इस मामले  
में कारणों सहित यह निविदा करना है कि क्या संविदा का  
निर्णय उपर्युक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया  
है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण।
- (ङ) माल का उद्गम देश।
- (च) संविदा की कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)।
- (छ) यदि कोई हो तो, भारतीय रुपये में भारतीय एजेंट के कमीशन  
की धनराशि (येन में)।
- (ज) वह शुद्ध लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुग-  
तान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।
- (झ) संभरकों के साथ की गई संविदा का नाम और दिनांक।
- (ञ) संभरक का नाम और पता।
- (ट) वे भुगतान शर्तें और सम्भावित तिथि जिनकी संविदाओं के  
अन्तर्गत भुगतान देय है।
- (ठ) सुपूर्तगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियां।
- (ड) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत  
किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका  
निपटान दर्शाते हुए)।
- (ढ) पोलवधान अनुबंध (वाह्मस्तरण/पार्टशिपमेंट की अनुमति दी  
गई है या नहीं निविष्ट कीजिए)।
- (ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।
- (त) कृपया यह स्पष्ट करें कि भारतीय बैंक, टोकियो के बैंकिंग  
प्रभारों को कौन वहन करेगा—आयातक अथवा संभरक।
- ब) आयातक द्वारा वचनबद्धता:—“हम एमद्वारा वचन देते हैं  
हैं कि हम विदेशी संभरक को देय धनराशि के समतुल्य रुपये

की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रिया विधि से  
और प्रचालित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे।

माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक परेक्षण के सुपूर्तगी प्राप्त  
करने से पूर्ण राशि सीधे ही जमा करवा दी जाएगी। विदेशी  
राष्ट्रिकों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे  
ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित  
किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे  
ही राशि जमा करवा दी जाएगी।”

अनुबन्ध-2

भुगतान के लिए प्राधिकरण सं.

संख्या—एफ

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय,  
आर्थिक कार्य विभाग  
नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,  
टोकियो शाखा,  
टोकियो (जापान)

विषय:— 1988-89 के लिए 611 मिलियन येन की जापानी अनुदान  
सहायता के अन्तर्गत उपस्कर स्थापित करने यातायात के  
लिए आवश्यक शैक्षिक प्रौद्योगिक उपस्करों और सेवाओं—  
का आयात।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 21-4-1988 को किए गए समझौते की शर्तों  
के अनुसार आपको एमद्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा संलग्न ध्यौरे  
के अनुसार सर्वश्री—को—येन  
धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी) की पावती के  
बारे में संभरक को सूचना दें इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति  
जापान सरकार आयातक बैंक भारतीय दूतावास टोकियो और इस मंत्रा-  
लय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परि-  
शिष्ट में यथा-संकेतिक लवान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपको देय बैंकिंग प्रभार जिनमें दस्तावेजों पर  
लगने वाला प्रभार और विदेशी संभरकों, बैंकों के प्रभार शामिल है,  
यदि कोई हो, आयातक के बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लवान दस्तावेज  
आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो  
इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और आयातक के बैंक को  
भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए  
प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संगोहन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र—तक वैध रहेगा।

भववीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक—जो उनके पत्र सं.-----  
दिनांक-----के संदर्भ में। उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे बैंकों से परफार्म दस्तावेजों की सुपूर्दी लेने से पूर्व अपने बंकरों के माध्यम से रुपये निशेन आदि को जमा करवाने की व्यवस्था करें। यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमा शुल्क प्राधिकारियों और पतन के प्राधिकारियों से मात्र की सुपूर्दी सीधे ही प्राप्त कर ली हो, तो वहाँ सुपूर्दी प्राप्त करने से पूर्व घनराशि जमा करवाने चाहिए। विदेशी संस्करणों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसा ही भुगतान के लिए बोतल प्रमुखित किए जाते हैं वैसे ही घनराशि जमा करा देनी चाहिए। जोध ही और सही रूप से घनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाहें-सिंग जनों में उल्लिखित कार्रवाई की जाएगी।

2. आयातक का बैंक-----। उन्हीं विदेशी जिना-जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो से दस्तावेज प्राप्त करने पर जायानी संस्करणों को येन भुगतान के समतुल्य रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संस्करणों को चुकाई गई घनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संस्करणों को भुगतान करने की तिथि की यथा-व्यक्ति परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संस्करण को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को प्रदायगी करने की तिथि तक सरकार के लेख में तुल्य रुपया जमा करने की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83, 35-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 26-8-1983 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18 प्रतिशत की दर से व्याज भी सरकारी लेख में जमा करना होगा। व्याज दोनों दिनों के लिए वेय होना अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संस्करण को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिस दिन सरकारी लेख में रुपया निशेन किया जाता है (यदि इस दर में कोई परिवर्तन होता तो इसकी सूचना तुरन्त दी जाएगी)। इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सीमाशुल्क निकासी के लिए आयातक को दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह घनराशि जमा कराई जाती है।

बालाग के बाएं कोने में कोड नं. 5130000009 दर्शाते हुए ये घनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीन हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा, या इसकी अनुबंधी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीय-कृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीन हजारी शाखा दिल्ली-6 (भद्रेशिती और मोदाता) के नाम में और उसकी देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका व्याज सार्वजनिक सूचना सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 की जतों की ओर दिनाया जाना है। लेखा शीर्ष जिसमें घनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपो-जिट्स एण्ड एक्वासिज-843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसेक्ट्री एक्वा परचेजिस इन्डर ग्रांट एण्ड क्रोम वि गवर्नमेंट आफ जानन फार 1988-89 इन्डर डिटेल्ड हैड 611 मिलियन येन ग्रांट एण्ड फार परचेज आफ एजुकेशनल टेक्नोलोजी एक्विपमेंट एण्ड सर्विसिस नेसेसरी फार इन्स्टालेशन/ट्रांसपोर्टेशन आफ भी इक्विपमेंट है।

जिस मामले में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीन हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा 219 G1/89-2

किया जाता है उन्हें बालाग की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना दिप्पनी का पूर्ण निवरण देते हुए प्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),  
पहली मंजिल, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग,  
संघद मार्ग, नई दिल्ली-110001.

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर सैंक्रेटिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-1968 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उन्हीं पते पर भेजी जानी चाहिए सभी मामलों में व्याज की चकाई गई घनराशि और जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है और उनके साथ जमा किए गए रुपया का पूरा ब्योरा इन बिना को भेजा जाएगा। वैधान प्रसार जिनमें समुद्रपार संस्करण के बैंकर के प्रमारी शामिल है, यदि कोई हो तो, बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा पात्रे ही निर्धारित किए जाएंगे।

3. भारतीय दूतावास, टोकियो।

4. अवर सचिव, (टी सी), वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

(लेखा अधिकारी)

## MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 94-ITC(PN)|88-91

New Delhi, the 25th January, 1989

Sub : Licensing Conditions for import of equipment and services under Japanese grant aid for 1988-89 :—(1) Yen 641 million for improvement of medical equipment of regional cancer centres; and (2) Yen 611 million for improvement of Educational Technology equipment of Indira Gandhi National Open University.

F. No. IPC/23(51)|88-91.—The terms and conditions governing import of equipment and services under Japanese grant aid for 1988-89 (1) Yen 641 million for improvement of medical equipment of regional cancer centres; and (2) Yen 611 million for improvement of Educational Technology equipment of Indira Gandhi National Open University, as given in Appendix to the Public Notice are notified for information.

K. V. IRNIRAYA, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE  
PUBLIC NOTICE NO. 94-ITC(PN)|88-91 DATED  
25-1-1989

Licensing conditions for purchase of medical equipment for Regional Cancer Centres and services necessary for installation/transportation of the equipment to ports in India and those for internal transportation therein under the Japanese grant aid of Yen 641 million for 1988-89 for improvement of medical equipment of regional cancer centres.

**Section I. General Conditions**

(i) The Japanese grant aid of Yen 641 million for 1988-89 is intended to be used for :—

- (1) Import of CT Scanners and supplementary equipment of regional cancer centres and services necessary for installation/transportation of the equipment (Yen 406.4 Million)
- (2) Import of Diagnostic equipment for the Madras Cancer Institute and services necessary for installation/transportation of the equipment (Yen 234.6 Million)—Out of Yen 234.6 Million an amount of Yen 26.5 Million is earmarked for procurement of Consultancy Services from Japan.

(ii) The import licences under this grant aid should be issued for an amount not exceeding Yen 705 Million (CIF) in favour of the importer and should bear the superscription "Yen 641 Million Japanese Grant Aid for 1988-89". The licence code for the first and second suffix will be "SJN". However, no import licence is required for items covered under O.G.L.

(iii) The equipment and services should be produced only from Japan/India under this grant aid. The purchase order should be placed only on the Japanese suppliers.

(iv) The import licence will be issued on CIF basis with initial validity upto 31-3-1989.

(v) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese Suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :

"delivery to be completed by 15-3-1989"

(vi) The contract value (C&F/FOB basis) should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agents' Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency.

The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(vii) The purchase contract should be entered into only in Japanese Yen with the Japanese nationals.

(viii) The procurement of goods and services under this grant aid should be done on the basis of an open tender confined to Japanese suppliers and the contract awarded to the lowest evaluated and technically acceptable bidder. In case it is proposed to procure the goods and services under this grant on direct negotiation basis prior approval of the Government of Japan may be obtained through the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

**Section II** The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :

(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 8th November, 1988 between the Government of India and Government of Japan concerning the Grant Aid of Yen 641 million for 1988-89 and will be subject to the approval of both the Governments.

(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorization to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1988-89.

(iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

(iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese suppliers should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

**Section III. Contract Approval by Governments of India and Japan.**

(i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (TC), Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 5 copies of the contract (one original and 4 photocopies) duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photocopies complete in all respects together with two copies of the tender evaluation report and two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

(ii) The Ministry of Finance (DEA), Japan Section will arrange to send two copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1988-89 of Yen 641 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

(iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the

Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

(v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be paid by the Embassy of India, Tokyo on behalf of importing Department. Rupee equivalent of these charges will be paid by the importing Deptt. to the Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, New Delhi on receipt of suitable advice from the CAA&A, New Delhi.

#### Section IV. Responsibility for rupee deposit

(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (o) in Annexure I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen payments made to the Japanese supplier is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

The Exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are currently deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further A/P to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. No interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government Departments. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-8443-Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan—for 1988-89"—Grant for purchase of the medical equipment and services necessary for the installation/transportation of equipment.

219 GI/33--3

(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/76 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of Payment to the Japanese supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite 'S' Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

## Section V. Miscellaneous provisions

## (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid.

The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

## (ii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure & under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

## (iii) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1988-89 from Japan.

## (iv) Breach or violation

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

## (v) List of Annexure :

Annexure-I—Request for issue of A/P

Annexure-II—Form of A/P.

## ANNEXURE I

## "REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
UCO Bank Building, 1st Floor,  
Parliament Street,  
New Delhi-110001.

Subject.—Purchase of medical equipment and services necessary, for the installation/transportation of the equipment under the Japanese Grant Aid of Yen 641 million for 1988-89.

Sir,

In connection with the import of above mentioned equipment from Japan under the above mentioned

Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese suppliers concerned:—

- (a) Name and address of Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid
- (c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F or FOB value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F or FOB value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) No. & date of the contract with Japanese suppliers.
- (j) Name and address of the Japanese Supplier.
- (k) Payment terms & probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/partshipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of Importer's bank in India.
- (p) Understanding by the importer.—"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made properly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign supplier are approved by us and the payments made to the suppliers".

Yours faithfully,

## ANNEXURE II

F. No.

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Economic Affairs

New Delhi, the ..... , 198

To

The Bank of India,  
Tokyo Branch,  
Tokyo (Japan)

Subject : Purchase of equipment and services necessary for the installation/transportation of the equipment under Japanese Grant Aid of Yen 641 million Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sir,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated ..... entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen..... to M/s. .... as per details given in the appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payment to the Suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including, charges for handling documents and charges of Overseas Suppliers, Bankers if any payable to you by the importer, will be paid by the Embassy of India, Tokyo.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's Bank.

6. No amendment to this A/P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto .....

Yours faithfully,  
(.....)  
Accounts Officer

Copy forwarded to :-

1. Importer.....with reference to their letter No. .... dated .....

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign Nationals, the deposits should be made

as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing conditions.

2. Importer's Banker ..... They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment of the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated the 17th January 1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Any change in this rate will be intimated if and when made. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the SBI, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the SBI or its subsidiaries or any one of the Nationalised Bank (Drawer) drawn on and made payable to the SBI, Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 233-ITC(PN)/68 dated the 24th October, 1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-71, No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/70 dated the 12th October, 1976. The head of account to be credited is "K-Deposits & Advances-8443-CIVIL Deposits-Deposit for purchases etc. abroad purchases under Grant Aid from Government of Japan for 1988-89" under detailed head "641 million grant aid for purchase of the medical equipment and services necessary for installation/transportation of equipment".

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi of the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October 1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

3. The controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance Department of Economic Affairs 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalent deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

Banking charges of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers, bankers, if any, would be paid by the Embassy of India, Tokyo, on behalf of the Importing Deptt. Rupee equivalent of these charges will be calculated in the above manner and deposited in favour of controller of Accounts, Ministry of External Affairs,

New Delhi for this purpose CAA&A will issue suitable advices to the Department.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TC), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(—————)  
Accounts Officer

Licensing Conditions for purchase of Educational Technology equipment and services necessary for installation/transportation of the equipment for Indira Gandhi National Open University (IGNOU) under Japanese Grant Aid for 1988-89 of Yen Six hundred and eleven Million (Yen 611,000,000).

#### Section I. General Conditions :

(i) The Japanese Grant Aid for 1988-89 of Yen 611 million (C&F) is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for purchase of educational technology equipment and services necessary for the installation/transportation of the equipment by the Indira Gandhi National Open University (IGNOU).

(ii) The import licence should be issued for an amount not exceeding Yen 672 million (CIF) in favour of the importer, and should bear the super-scription "Yen 611 million Japanese Grant Aid for 1988-89". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". No import licence is required for items covered under O.G.L.

(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels, payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

(iv) The equipment and service should be procured only from Japan/India under this Grant Aid. The purchase order should be placed only on the Japanese suppliers.

(v) The import licence will be issued on CIF basis with validity upto 31-3-1989.

(vi) The contract should provide for payment on cash basis i. e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 15-3-1989"

(vii) the contract value (C&F/FOB basis) should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency.

The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract

itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(viii) The purchase contract should be entered into only in Japanese Yen with the Japanese nationals or Japanese juridical persons controlled by Japanese nationals.

Section II. The following provisions should be specifically incorporated in the supply contract :—

(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 8th November, 1988 between the Government of India and Government of Japan concerning the Grant Aid of Yen 611 million for 1988-89 and will be subject to the approval of both the Governments.

(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorization to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1988-89.

(iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

(iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

#### Section III. Contract Approval by Governments of India and Japan.

(i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 5 copies of the contract (one original and four photocopies) duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

(ii) The Ministry of Finance (DEA), Japan section will arrange to send 2 copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1988-89

of Yen 611 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

(iii) On receipt of the contract approval from the Govt. of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

(v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittance to the BOI, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

#### Section IV Responsibility for rupee deposit.

(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 12% per annum for the first thirty days and at 18% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN) 83 dated 10-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposits are made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN) 74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN) 76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for

computing the rupee equivalent of the Yen payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN) 76 dated 17-1-76 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further A/P to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-844 Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan-for 1988-89". Grant for purchase of the educational technology equipment and services necessary for the installation of the equipment/transportation of equipment by the IGNOU.

(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN) 68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN) 68 dated 24-10-1968 and No. 152-ITC(PN) 71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN) 74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN) 76 dated 12-10-1976.

(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in Para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN) 71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN) 74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN) 76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars

should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the Japanese supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account)

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

**Note :** Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

#### Section V the Miscellaneous provisions

##### (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid

The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

#### (ii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

#### (iii) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1988-89 from Japan.

#### (iv) Breach or violation

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

#### (v) List of Annexures :

Annexure-I : Request for issue of A/P

Annexure-II : Form of A/P.

#### ANNEXURE-I

"Request for Issue of the Authorisation to pay"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
UCO Bank Building, 1st Floor,  
Parliament Street, New Delhi-110001

**Subject :** Import of educational technology equipment and services necessary for the installation/transportation of the equipment under the Japanese Grant Aid of Yen 611 million for 1988-89

Sir,

In connection with the import of above mentioned equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese Supplier concerned :—

(a) Name and address of Indian Importer.

ANNEXURE-II

No. F.

## GOVERNMENT OF INDIA

## MINISTRY OF FINANCE

Department of Economic Affairs

New Delhi, the .....

(b) Number date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F or FOB value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F or FOB value (in Yen) for which the A/P is required.

(i) No. & date of the contract with Japanese Suppliers.

(j) Name & address of the Japanese Supplier

(k) Payment terms & probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transshipment|partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of Importer's bank in India.

(p) Undertaking by the importer :—"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (Material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to the suppliers."

Yours faithfully,

To

The Bank of India,

Tokyo Branch,

Tokyo (Japan)

Subject :—Import of educational technology equipment and services necessary for the Installation|transportation of the equipment under Japanese Grant Aid of Yen 611 million for 1988-89. Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated \_\_\_\_\_ entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen—\_\_\_\_\_ to M/s. —\_\_\_\_\_ as per details given in the appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including, charges for handling documents and charges of Overseas Suppliers, Bankers if any payable to you by the importer, will be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendment to this A/P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry

7. This A/P will remain valid upto \_\_\_\_\_.

Yours faithfully,

( )

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer ————— with reference to their letter No. ————— dated —————.

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign Nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing conditions.

2. Importer's Banker———. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN) 76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 12% per annum for the first thirty days and at the rate of 18% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Govt. account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of the Public Notices No. 31-ITC (PN) 83 dated 18-1-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee

and Payee). In this connection their attention is also invited to the Provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN) 68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC (PN) 71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC (PN) 74 dated 31-5-1974 and 103-ITC (PN) 76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is 'K-Deposits & Advances-8443 Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad 'Purchases under Grant Aid from Government of Japan for 1988-89' under detailed head "Yen 611 million grant aid for purchase of the educational technology equipment and services necessary for installation/transportation of the equipment".

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash of the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC (PN) 71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas Suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

3. Embassy of India, Tokyo.

4. The Under Secretary (TC), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

( )  
Accounts Officer